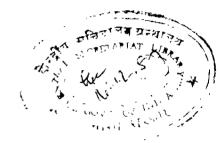


असाधाररा EXTRAORDINARY

भाग II—सबस 3—उब-सबस (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)



शाधिकार ते प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

w. 486] No. 486] न**ई जिल्ली,** सोमवार, सितस्बर 21, 1987/ भाव 30, 1909

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 1987/BHADRA 30, 1909

इस भाग में भिन्म पूळ संख्या वी जाती है जिससे कि यह असग संजलन को दूर्ण के रखा जा सकी

Separate Paging is given to this Part in order that at may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पका)

तई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1987

अधिसूचना

गा.का.नि. 807(अ). --- केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 वा 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के माथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त मिन्तयों का प्रयोग करते हुए एत्स्ट्र्बारा कीचीन पत्तन के लिये न्यासियों के मंडल द्वारा निर्मित धौर इस अधिसूचना के माथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित कोचीन पत्तन कर्मचारी (भवन निर्माण इत्यादि के लिये पेशनी अनुवान) संज्ञोणन जिनियम, 1987 को अनुमोदन प्रयोग करती है।

 ये विनियम इस अधिमूचना के राजकीय राजपक्ष में प्रकाशन की नारीच से प्रवृत्त होंगे।

> [फा.सं. पी सम्भ्यू/पी ई आप-35/85] पी.एम. आकाहम, अपर मणिव

कोचीन पोर्ट कर्मचारी (मकान निर्माण आदि के लिमे अग्रिम अनुदान) का मंगोधन विनियम, 1986

कोबीन पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की घारा 28 द्वारा प्रदत्त कवितयों का प्रयोग करते हुए, कोबीन पोर्ट कर्मचारी (मकान निर्माण आदि के लिये अग्निम अनुदान) विनियम, 1971 का और संशोधन के लिये निस्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:---

- इत विनियमों का नाम कोचीन पोर्ट कर्मचारी (मकान निर्माण आदि के लिये अग्रिम अनुधान) संशोधन विनियम 1986 है।
- 2. वितियम 3 में वर्तमान नोट को नंबर (1) लगा दें नथा निस्त-लिखित नोट नं. (2) के रूप में पहा जाये।
 - नोट (2) "बोर्ड की सेवा में पुन. नियोजित सेवा विमुक्त सैनिकों के बारे में 10 माल के लगातार सेवा की गणना करने में उनके सैनिक सेवा की अवधि को भी जोड़ दिया जाये बशर्ते कि वे परिवीक्षा समय टीक तरह से पूरा किया हो।"

- 3. (क) कोषीन पोर्ट कर्मजारी (सकान निर्माण आदि के लिये अग्रिम अनुदान) विनियम 1971 विनियम 4 के उप विनियम (क) में निम्नलिखित जोड़ा जाये:--
 - (क) निर्माण करने या खरीदने बाले घर या फ्लैट के मूल्य का उच्चतम सीमा निम्मलिखित हैं । परम्सु घर के मंबध में आवासी फ्लैट का मूल्य इममें से अपवर्णित हैं।
- (1) कर्मचारी जिसका मूल जेतन 100 महीने 1,25,000/-के लिये 80,000 ठ. तक हो
- (2) कर्मचारी जिसका मूल वेतन 100 महीने 2,00,000/-के लिये 80,000 र. से ज्यादा हो लेकिन 1,70,000 तक
- (3) कर्मणारी जिसका मूल वेतन 100 महीने 3,00,000/-के लिये 1,70,000 रु. से ज्यावा हो

तथा आवेदक किसी भी प्राधिकारी, पुनर्वास विभाग या केन्द्र या राज्य सरकार के आवाम योजना से किसी ऋण या पेशगी इस उद्देश्य के लिये न प्राप्त किया हो बशर्ते कि आवेदक द्वारा वाच्छित ऋण या पेशगी इस नियम के अधीन उनको मिलने के योग्य से अधिक न होगा। पेशगी के सिये आवेदन देने के सिये वह हकदार है, शर्त है कि उनके हित में जो ऋण या पेशगी शेष है अयाज सहित सम्बन्धित प्राधिकारी या निकाय को एक मृश्त में दिया जाये।

- (खा) उप विनियम (अ) के बाद निम्नलिखित उप विनियम ओड़ विया जोये।
- (अ)(1) महकरण संघ हाउसिंग सोसाइटी की सदस्यता द्वारा घण प्राप्त कर्मचारियों ऊपर (ए) में बताये मार्तों के अनुसार मकान निर्माण के लिये पेमगी लेने के लिये योग्य हैं। ऐसे कर्मचारी 70,000 रुपये से ज्याचा सकान निर्माण पेमगी के लिये वैयक्तिक वैद्य प्रम के अतिरिक्त निम्निलिखत दस्तावेज प्रस्तुत करना है।
- (अ) स्वरविश्वि जमा करने (जब कभी उपलब्ध हो) के साथ साथ घर या पर्पेट बन्धक करने का एक करार भी देना वाहिये।
- (आ) निष्चित दर पर ब्याज सहित मूलघन की राणि के लिये क्वन
- 4. विनियम 4 के उपविनियम (ख) में "75 महींने के बेतन" वाक्य के स्थान पर "100 महीने के बेनन" प्रंकों तथा अक्षरों में प्रतिस्थापित किया जायें।
- 5. विनियम 5 के उप विनियम (ख्र) में "उसके नामिक वेतन के 75 बार" में स्थान पर "मासिक वेतन के 100 बार" प्रकों तथा अकारों में प्रतिस्थापित किया जाये।
 - 6. विनियम 6 के उपविनियम (खा) में
 - (1) ग्रंकों तथा अक्षरों के "मासिक बेतन के 75 बार" के स्थान पर "मासिक बेतन के 100 बार" मंकों तथा अक्षरों में प्रति-स्थापित किया आये।
 - (2) 'केन्द्रीय सिविल इतिस (संशोधित) नेतन नियम 1960'' के बाथ ''एवं परिवार पेंगन'' नाक्य जोड़ दिया जाये।
 - (3) "70,000" तथा "25,000" के स्थान पर 1,25,000 नथा 40,000 कमशः प्रतिस्थापित किया जाये।
- सिनियम ६ के उपविनियम (इ) में निम्निलिखन वाक्ष्य प्रति-स्वापित नियम जाये।

"निम्मलिखित आधार पर अनिपूर्ति चुकाने की कमला परिकलित किया जायेगा।

णेष रहित सेवाकी अवधि

मनिप्रित देने का स्लाब

कः 20 वर्ष के बाद सेवा निबृत्तः कर्मचारियों मूल येतन के 50%

खः 10 वर्ष के बाद सेवा निवृत्त कर्मचारियों लेकिन 20 वर्ष से ज्यादा

मूलवेतन के 60 % डी. सी. आर.जी. के 80 % भी समायोजित किया

ग. 10 **पर्ष के अन्दर सेवा निवृ**त्त कर्मे**वारियों**

भूलवेतन के 66 2/3% ही.सी. आर. जी, के 90% भी समा-योजिन किया जायेगा।"

- 8. वितियम 87 के उपवितियम (4)(i) में "75" तथा "70,000" के स्थान पर "100" तथा "1,25,000" अक्षरों को प्रतिस्थापित किया जाये।
 - विनियम 8 को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाये .---

पेशागी का व्याज, पेशागी लेने के दिन से साधारण क्याज के दर पर निष्टिबल किया जायेगा। हर महीने के श्रीतिम दिन में जो राशि शेय रह जायेगा, उस रक्तम पर व्याज लिया जायेगा।

इन विनियमों के अनुसार पोर्ट कर्मचारियों को दिये जाने वाले मकान निर्माण पेशनी के क्याज का दर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को समय समय पर दिये जाने वाले के समान होगा।

10. विनियम 11(क) के अधीन उपविनियम (5) में निम्नलिश्वित जोड़ दिया जाये।

''आवेदफ जो विभागीय क्वार्टसें में रहता है, उन्हें एक बचन पल देना है कि वह कोवीन निगम में या उप शहरी क्षेत्र में जो अपने पोर्ट के कार्यास्थल से सड़क से या जल मार्ग से 20 कि.मी. के अन्दर घर बनाया या खरीदा जाये तो वह विभागीय क्वार्टमें को मकान बनाने या खरीवने के नुरन्त बाद ही खाली कर दिया जायेगा।

- 11. विनियम 11 में धारा (1) की उपधारा (च) में निम्निमिखित प्रतिस्थापित किया जाए :----
 - "(1) भूमि या भवन एवं परिसर, यथाप्रसंग, का क्रय होते ही स्थत्व विलेख जमा करके बन्धक के उत्तरदायिस्य निभाना है एवं दस्तावेज की सुरक्षित परिरक्षा की जायेगी।"
 - नोट: मकान निर्माण अधिम अनुदान के संबंध में सभी पिछले मामले जिसमें स्वरंव विलेख जमा करके साम्यिक बन्धक का उत्तर-यायित्व निभाना इस उप धारा के अन्वर आ आयेगा परन्तु जिस मामले में बन्धक स्वरंव का पंजीकरण हुआ है वह आगे वैखने की जरूरत नहीं।
- 1.2- विनियम के फार्म सं. 1 के स्थान पर परिकाष्ट-II में गलग्न फार्म प्रतिस्थापित किया जाये।

पाद टिप्पणी :

नौबहन तथा परिवहन मंत्रास्य के 12 जुलाई, 1971 के पत्न सं. 6 पी ई (10)167 के अनुसार मुख्य विनियमों का अनुमोदन किया तथा 14-9-1971 के फेरल के राजपत्न में इस अधिसूचना में प्रकाणित किया था।

फार्म लं. 1

सेवा में

जन्मक्ष कोचीन पोर्ट ट्रम्ट, कोचीन-682 009

प्रिय महोदय,

दस्तावेजों की मुची

١.

2.

3

स्यानः

दिनांक :

भवदीय

(पवनाम)

सम्बद्ध कार्यालय

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, 21st September, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 807(E),—In exercise of the powers conferred by subsection(1) of section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963(380f 1963), the Central Government hereby approved the Cochin Port Employees (Grant of advances for building of Houses etc.) Amendment Regulatins, 1987 made by the Board of Trustees for the Port of Cochin and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[File No. PW/PER-35/85]
P. M. ABRAHAM, Addl. Secy

COCHIN PORT EMPLOYEES (GRANT OF ADVANCES FOR BUILDING OF HOUSES ETC. (AMENDMENT REGULATIONS 1986.)

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) Cochin Port Trust Board hereby makes the following Regulations further to amend Cochin Port Employees (Grant of advances for building of houses etc.) Regulations, 1971 namely:—

- These Regulations may be called the "CochinPort Employees (Grant of Advances for building of houses etc.) Amendment Regulations ,1986".
- 2 In Regulation 3, the existing Note may be renumbered as (1) and the following may be added as Note (2)—

NOTE (2): "in the case of Ex-servicemen re-employed in Board's service, the military service rendered by them shall also be taken into account for reckoning the period of ten years continuous service, provided they have completed probationary period satisfactorlly."

- 3. (a) In the Cochin Port Employees (Grant of advances for building of Houses etc.) Regulations, 1971 for sub-regulation (a) of Regulation 4, the following shall be substituted:
- (a) The cost of the House or at to be built/purchased excluding the cost of residential flat in the case of a house shall be within the following ceiling limits:
 - (i) For employees whose basic pay for 100 months is upto Rs 80,000 -- Rs. 1,25,000/-
 - (ii) For employees whose basic pay for 100 months exceeds Rs. 80,000 but is up to Rs. 1,70,000 Rs. 2,00,000/-
 - (iii) For employees whose basic pay for 100 months exceeds Rs. 1,70,000/- Rs. 3,00,000/-

and the applicant should not have availed of any loan or advance for the purpose from any other authority or body such as the Deptt. of Rehabilitation or a Central or a state Housing Scheme provided, that where the loan or advance already availed of by an applicant does not exceed the amount admissible under these rules, it is open to him to apply for an advance under these rules subject to the condition that he undertakes to repay the outstanding loan or advance together with interest if any thereon forthwith, in one lumpsum to the authority or body aforesaid.

- (b) After sub-regulation (a) the following sub-regulation shall be inserted:—
- (a) "(i) Employees who acquire houses through membership of cooperative Group Housing Societies shall also be eligible for grant of HBA upto the limit as in (a) above. Such employees shall however be required to furnish the following documents in addition to personal Bond for drawing House Building Advance beyond the limit of Rs. 70.000/-
- (a) An agreement to mortgage the house or flat followed by deposit of title deeds (as and when available);
- (b) Promissory Note in respect of the amount of the principal plus interest at the specified rates."
- 4. In sub-regulation(b) of Regulation 4, the words "Seventy five months Pay" shall be substituted by the words and figures "Pay for 100 months"
- 5. In sub-regulation (b) of Regulation 5, the words "Seventy five times his monthly pay" shall be substituted by the words and figures "100 times monthly pay."
 - 6. In sub-regulation (b) of Regulation 6
 - (i) The words and figures "75 times the monthly pay" shall be substituted by the words and figures "100 times monthly pay."
 - (ii) The words "and family pension" shall be inserted after the words "Central Civil Service (Revised) Pay Rules, 1960."
 - he figures "70,000/- and 25,000/-"shall be substituted e figures 1,25,000/- and 40,000/-respectively.

- Sub-Regulation (e) of Regulation 6 shall be substituted by the following:—
- "The repaying capacity will be computed on the following basis.

Length of remaining service. Slab of repaying capacity

- (a) Officials retiring after 50% of the basic pay 20 years.
- (b) Officials retiring after 60% of the basic pay. 10 years but not later 80% of the DCRG may also than 20 years be adjusted.
- (c) Officials retiring within 10 years. 66!2/3% basic pay 90% of DCRG may also be adjusted."
- 8. In sub-regulation (4) (i) of Regulation 7, the figures "75" and "70,000/-" shall be substituted by the figures "100" and "1.25,000/-" respectively.
 - 9. Regulation 8 shall be substituted by the following :--

Interest on advance shall carry sample interest from the date of advance. The amount of interest shall be calculated on the balance outstanding on the last day of each month.

The rate of interest on House Building advance granted to the Port employees under these Reglations will be the same as made applicable by the Central Government to its employees for this purpose from time to time.

- The following shall be inserted as sub-regulation -(v) under Regulation 11 (a).
 - "An undertaking from an applicant who has been allotted Departmental quarters and also wants to construct or purchase a house within the limits of Cochin Corporation including the sub-urban area coming within 20 Kilometres by the shortest route by road and or water from his normal place of duty in the Port, to the effect that he/she will vacate the Departmental Quarter immediately on purchase of house or on completion of construction of the house as the case may be."
- 11. In Regulation 11, for clause (i) of sub-regulation (f) the following shall be substituted: -
 - "(i) The prescribed charge by way of mortgage by deposit of Title deeds is created immeditely on 'purchase of land or the house and permises, as the case may be, and documents kept in safe custody."
 - Note: All the past cases in which-charge by way of equitable mortgage by deposit of title deeds has been created in respect of House Building Advance sanctioned will come within the purview of this subclause and the cases where mortage deeds have been registered shall not be re-opened.
- 12. Form No. 1 of the Regulations shall be substituted by the Form attached in Appendix-II

FOOT NOTE: The principal Regulations were approved vide Ministry of Shipping & Transport Letter No. 6-PE(10)/67 dated 12th July, 1971 and the notification was published in the Kerala Gazette dated 14-9-1 971.

....office to which attached)

Date:

~~~	-		* * *	
L ( )	v	N.A	NΩ	

	FORM NO-1
Γο	
The Chairman,	
Cochin Port Trust,	
COCHIN-682 009.	
Dear Sir,	
following documents with intent to create expressions (Rupees	at Willingdon Island in the city of Cochin on
	LIST OF DOCUMENTS
1.	
2.	
3.	Yours faithfully,
Place:	(Designation